उत्तर प्रदेश में मोहन सराय से मुगल सराय तक बाई-पास का निर्माण

1910. **श्री मोहम्मद मसूद खानः**
श्री वसीम अहमदः
श्री अखिलेश दासः
श्री मोहम्मद आज़म खानः

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वाराणसी (उ०प्र०) में मोहन सराय से मुगल सराय तक जी०टी० रोड पर बाई-पास तथा गंगा नदी पर पुल बनाने का कार्य किस तिथि से शुरू किया गया था और इसके पूरा होने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई थी;

(ख) उपरोक्त परियोजना के लिए शुरू में कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी और अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) इस परियोजना की प्रगति का प्रतिशत ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना को समय से पूरा न करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त परियोजना को पूरा करने के लिए अन्तिम तिथि क्या निर्धारित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) परियोजना के शुरू होने और पूरा होने की प्रारंभिक तारीखें इस प्रकार हैं:—

	शुरू होने की तारीख	पूरा होने की प्रारंभिक तारीख
मोहन सराय से मुगल सराय तक बाइपास सड़क	1.11.87	1.4.91
गंगा नदी पर पुल	31.12.88	30.12.92

(ख) यह परियोजना प्रारंभ में 49.92 करोड़ रु० की लागत पर स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना की अनुमोदित संशोधित लागत 122.59 करोड़ रु० है। जनवरी, 1997 तक 97.15 करोड़ रु० का व्यय हुआ।

(ग) से (ङ) बाईपास के निर्माण में विलम्ब मुख्यतः मूल ठेकेदार द्वारा कार्य न करने के कारण हुआ। तदनुसार उसका ठेका रद्द कर दिया गया और यह कार्य जून, 1993 में सोमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया है। पुल के निर्माण में विलम्ब मुख्यतः विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण हुआ जो कार्य शुरू करने से पहले डिजाइन में संशोधन के कारण आवश्यक हो गया था। बाईपास के निर्माण में प्रगति लगभग 50% और गंगा नदी पर पुल के निर्माण के मामले में लगभग 95% है। इस परियोजना को दिसम्बर, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कपड़ा उत्पादन

1911. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1995-96 में देश में मिलों, विद्युतकरघा, हथकरघा और हौजरी क्षेत्रों में कुल कपड़ा उत्पादन का क्रमशः 6.42 प्रतिशत, 54.68 प्रतिशत, 22.89 प्रतिशत और 16.01 प्रतिशत उत्पादन किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार का क्या अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि इन विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए गए कुल वस्त्र उत्पादन का कितना-कितना प्रतिशत निर्यात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों द्वारा निर्यात किए गए कपड़े की कुल मात्रा और इस प्रकार अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान, देश में कपड़े के उत्पादन में मिल, हथकरघा,

विद्युतकरघा तथा हौजरी का प्रतिशत भाग क्रमशः 6.42%, 22.89%, 54.68% तथा 16.01% था। खादी, ऊन तथा रेशम फैब्रिक्स के उत्पादन को कुल कपड़े के उत्पादन में नहीं माना गया है। यदि कुल कपड़े के उत्पादन (खादी, ऊन तथा रेशम फैब्रिक्स सहित) पर विचार किया जाए तो वर्ष 1995-96 के दौरान मिल, हथकरघा, विद्युतकरघा, हौजरी, खादी, ऊन तथा रेशम क्षेत्रों का भाग क्रमशः 6.33%, 22.58%, 53.94%, 15.80% तथा 1.35% (खादी, ऊन तथा रेशम क्षेत्र) होगा।

(ग) और (घ) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात और उत्पादन के उपलब्ध आंकड़ों से निर्यात किए जा रहे कपड़े का प्रतिशत 19.6% बनता है।

वर्ष 1995-96 के दौरान क्षेत्र-वार निर्यात किए जा रहे कपड़े की कुल अनुमानित मात्रा तथा मूल्य के आंकड़े निम्न प्रकार हैं।

	मात्रा मि॰ वर्ग मी॰ में	मूल्य (मि॰ रु॰)
मिल / विद्युतकरघा	3006.50	75,254.80
हथकरघा	343.76	15.316.10
निटिड फैब्रिक्स	3.90	113.33
सिले-सिलाए परिधान	2836.62	148,063.90
रेशम	57.10	8,431.14
कुल:	6247.88	247,179.27

National Policy on Silk

1912. SHRI M. RAJASEKARA MURTHY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce (1995-96) in its 14th Report has recommended to formulate a national policy on silk; to constitute a working group to evolve a long term import and export policy to promote silk and silk products' export, thrust on bivoltine silk as against multi-voltine silk with a view to produce best quality of silk at the lowest prices and that in view of long term requirement step should be taken to evolve superior races; and

(b) if so, the taken so far on the above recommendations?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) Yes, Sir.

(b) The current textile policy already includes broad policy guidelines relating to silk as well. However to review the present EXIM policy on silk and silk products, a Working Group had been constituted. The efforts of the State Sericulture Departments for producing bivoltine silk have been supplemented by the Central Silk Board (CSB) through its continuing research efforts and also by field trials of bivoltine elite breeds, supply of bivoltine hybrid layings and extension of free disinfection services of the rearing houses and equipments to bivoltine hybrid reaers.

Silk Production

1913. SHRI M. RAJASEKARA MURTHY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the State-wise production of (i) raw silk; (ii) spun silk yarn; (iii) noil silk yarn (iv) silk waste based on production of raw silk during the last three years (year-wise figures to be furnished);

(b) the exports and imports of the (i) raw silk; (ii) spun silk yarn; (iii) noil silk yarn; (iv) silk waste during the last three years (year-wise figures to be furnished);

(c) the average import and export prices separately of the above 4 varieties, year-wise; and

(d) whether graded raw silk A, 2A, 3A etc. are produced in the country; and if so, the total production, year-wise, for three years?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) A statement showing the State-wise production of raw silk, silk waste, spun silk yarn and noil silk yarn year-wise during the last three years between 1993-94 to 1995-96 is attached as Statement-I (*See* below)

(b) and (c) A statement showing the